भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2588

जिसका उत्तर बुधवार 9 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए सुविधाएं

2588. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए सुविधाएं स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कम लागत की लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): वर्तमान में, सरकार द्वारा लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिए सुविधाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, फेम-इंडिया स्कीम के तहत गठित परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृति समिति द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत विशिष्ट परियोजनाओं पर, इस स्कीम के अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास तथा सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घटकों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु विचार किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने उपग्रहों और लॉन्च व्हीकल्स में उपयोगार्थ लिथियम-आयन बैटरियां विकसित की हैं और इनकों हाल ही के अंतरिक्ष मिशनों में पहले ही शामिल किया जा चुका है। चार प्रकार की बैटरियां नामतः 1.5 एम्पीयर घंटा (Ah), 5 एम्पीयर घंटा, 50 एम्पीयर घंटा, 100 एम्पीयर घंटा विकसित की गई हैं। इनमें से, इसरो ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) को 50 एम्पीयर घंटा लिथियम-आयन बैटरी की आपूर्ति की है। इसरो द्वारा विकसित लिथियम-आयन बैटरी 19 जनवरी, 2017 को इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नालॉजीज (एसआईएटी-2017) पर विचार-गोष्ठी में एक प्रोटोटाइप दुपहिया वाहन में सफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई थी।

******